HINDUSTAN TIMES, Delhi, 21.5.2025
Page No. 18, Size:(8.88)cms X (14.29)cms.

NHRC invites entries for its 11th annual competition

National Human Rights Commission invited entries for its 11th annual competition for short films on human rights. The last date to receive the entries is August 31. The winning entries will be awarded. The Short Film Awards scheme was instituted by the Commission in 2015. The scheme aims to encourage and acknowledge the cinematic and creative efforts of Indian citizens, irrespective of their age, towards promoting and protecting human rights. In all previous competitions, the Commission received tremendous responses.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 21.5.2025
Page No. 18, Size:(17.73)cms X (14.37)cms.

NHRC's online short- term internship programme begins

The National Human Rights Commission began its two-week online short-term internship programme. 80 university-level students from diverse academic disciplines from 21States and Union Territories have been shortlisted out of 1,795 applicants to participate in this programme. The two-week programme aims to provide a comprehensive understanding of the promotion and protection of human rights in the country.

NHRC, India Secretary General, Bharat Lal, in his address, said that youth are the torchbearers of India's 5,000-year-old civilisational ethos of empathy, compassion and justice. He urged the students to serve as ambassadors of justice, equality, and dignity, and encouraged them to leverage this opportunity to understand India's constitutional framework and advocate for human rights and dignity of all. He also urged them to focus on reflection over reaction and to make the best use of the opportunity to learn from experts to discover life's purpose.

HINDUSTAN TIMES, Chandigarh, 21.5.2025
Page No. 4, Size:(7.22)cms X (14.05)cms.

Police were inactive at some places: HC panel on Murshidabad riots

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

KOLKATA: A report by a committee set up by the Calcutta High Court for identification and rehabilitation of victims of anti-Waqf protests-related violence in West Bengal's Murshidabad district said that the local police were "inactive and absent" during the incidents at Dhulian on April 11.

It also mentioned that a local councillor directed the attacks at Dhulian town in Murshidabad.

The report, submitted to the high court by the three-member committee, stated that a garments mall in Dhulian was also looted.

Noting that the "main attack" occurred on the afternoon of April 11, the report said "Local police were completely inactive and absent."The panel, comprising Joginder Singh, Registrar, (Law), National Human Rights Commission (NHRC), Satya Arnab Ghosal, member secretary, West Bengal Legal Services Authority (WBLSA) and Saugata Chakraborty, Registrar, WBJS, submitted the report to the high court last week after visiting the affected areas and speaking to the victims as directed by the division bench hearing the matter.

The high court had on April 17 ordered the formation of the committee for the identification and rehabilitation of people displaced by the violence during the protests over the Waqf (Amendment) Act in Murshidabad district.

The division bench, comprising justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury, noted that the committee had stated in its report that "appointing qualified valuation experts is the only possible remedy to the state's failure to protect a section of its citizens.

"The victims of the affected areas need individualised and customised rehabilitation packages and for this, securing the services of valuation experts appears to be the sine qua non (an essential condition)," it said, according to the court.

Another report earlier submitted by the West Bengal government to the division bench hearing the petitions related to the Murshidabad violence detailed widespread incidents of violence between April 8 and April 12 by mobs in connection with protests over the Waqf Act.

It stated that following intervention by the police and civil administration, the situation in Suti, Dhulian, Samserganj and Jangipur was under control.

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 21.5.2025
Page No. 1, Size:(18.39)cms X (15.94)cms.

मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा के दौरान नदारद रही पुलिस

कोलकाता (भाषा)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 अप्रैल को धुलियान में हुई घटनाओं के दौरान स्थानीय पुलिस 'निष्क्रिय और अनुपस्थित' थी।

मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था। तीन सदस्यीय समिति द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि धुलियान में कपड़ों के एक शोरूम में भी लूटपाट की गई थी। 'मुख्य हमला' 11 अप्रैल की दोपहर को होने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय

■ कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति ने दी रिपोर्ट

पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार जोगिदर सिह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल है। समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से बात करने के बाद पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

AMAR UJALA, Delhi, 21.5.2025
Page No. 1, Size:(14.06)cms X (9.43)cms.

मुर्शिदाबाद हिंसा...हिंदुओं को बनाया गया निशाना, मूकदर्शक बनी रही पुलिस : रिपोर्ट

हाईकोर्ट की ओर से गठित जांच समिति ने कहा, हिंसा में तृणमूल नेता शामिल, विधायक के सामने ही घरों में आग लगाई

अमर उजाला ब्यूरो

कोलकाता। प. बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पिछले महीने भड़की हिंसा में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक नेता शामिल था। हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इस दौरान पुलिस कहीं मूकदर्शक बनी रही, तो कहीं मौके पर नहीं पहुंची। हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में यह हिंसा भड़की थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश सौमेन सेन और राजाबसु चौधरी की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को पेश रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हैं। बताया गया कि मुख्य हमला शुक्रवार, 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ, जिसका नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम कर रहा था। उसके साथ हजारों लोग थे। बेदवना गांव में 113 घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया, जो रहने लायक नहीं रह गए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और न्यायिक सेवा के सदस्यों वाली समिति ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि हिंसा का निशाना हिंदू समुदाय था। बेदवना गांव में तृणमूल विधायक अमीरुल इस्लाम भी आए और देखा कि किन घरों पर हमला नहीं हुआ है, फिर हमलावरों ने उन घरों में आग लगा दी। यह सब विधायक के सामने हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और मौके से चले गए। पीड़ितों ने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए 17 अप्रैल को समिति गठित की थी।

फाइल फोटो

पानी के कनेक्शन तक काटे ताकि आग न बुझा पाएं

रिपोर्ट के अनुसार, इलाके में बड़े पैमाने पर आगजनी, लूटपाट हुई और दुकानों व मॉल को नष्ट किया गया। हमलावर शमशेरगंज, हिजालताला, शिठलिताला, डिगरी के ही रहने वाले थे और अपना चेहरा ढंककर आए थे। हमलावरों ने पानी के कनेक्शन भी काट दिए, ताकि आग बुझाई न जा सके। हमले से गांव की महिलाओं में दहशत व्याप्त हो गई थी और उन्होंने दूसरी जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली।

मंदिरों को भी नुकसान : *जांच समिति ने कहा कि हिंसा के दौरान हमलावरों ने जमकर उत्पात मचाया। किराना, हार्डवेयर, बिजली और कपड़े की दुकानों के साथ ही मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। यह सब पुलिस थाने के 300 मीटर के दायरे में ही हुआ। अकेले घोषपाड़ा इलाके में ही 29 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। समिति ने यह रिपोर्ट प्रभावित गांवों का दौरा करने और पीड़ितों से बातचीत करने के बाद तैयार की है।*

हाईकोर्ट ने कहा-पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज मिले

पीठ ने कहा कि समिति ने रिपोर्ट में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज देने की जरूरत बताई है। इसका मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की सलाह भी दी है। यह भी कहा कि नागरिकों के एक वर्ग को सुरक्षा देने में नाकाम रही राज्य सरकार की ओर से अपनी विफलता की भरपाई करने का यही एकमात्र उपाय है।

■ **ममता सरकार ने भी सौंपी रिपोर्ट...दावा, पुलिस ने काबू किए हालात :** खंडपीठ को प. बंगाल सरकार ने भी एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है, पुलिस और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में स्थिति नियंत्रण में आई। रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 4 अप्रैल से ही मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 12 अप्रैल को शमशेरगंज में भीड़ ने हरगोविंद दास और उनके पुत्र चंदन दास की हत्या कर दी। शमशेरगंज में 11 अप्रैल को ही केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 12 अप्रैल को तैनाती बढ़ाई गई थी।

अमर उजाला की रिपोर्ट पर जांच समिति की मुहर

मुर्शिदाबाद हिंसा पर अमर उजाला ने बेदवना की बेदना शीर्षक से 20 अप्रैल को रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें बेदवना गांव में 113 घरों को जलाने की बात कही गई थी, जांच समिति ने इसका अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है।

ORISSA POST, Bhubaneswar, 21.5.2025
Page No. 5, Size:(6.48)cms X (9.71)cms.

QUINTUPLE MURDER IN SUNDARGARH

NHRC seeks report from DM, SP

UNITED NEWS OF INDIA

Kendrapara, May 20: National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action-taken report (ATR) from Sundargarh District Magistrate and Superintendent of Police regarding the brutal murder of five members of a nomadic family.

The incident occurred on the night of October 29, 2024, in the district, where five members of a nomadic family were killed, and five others were allegedly kidnapped.

Acting on a petition filed by civil rights advocate Radhakanta Tripathy, the apex rights panel issued the order Monday. Tripathy alleged that the victims, part of a group of approximately 20 family members residing in tents in Karamdihi village, were attacked while they were asleep. The family, seasonal visitors selling plastic mats, was reportedly targeted due to an illicit relationship involving one of the injured individuals.

The kidnapped persons reportedly include the injured man's second wife and four children.

The incident, according to the complaint, underscores the systemic marginalisation of Denotified and Nomadic Tribes (DNTs) and calls out the alleged inaction of both the Odisha government and Central authorities, framing it as a violation of human rights.

Tripathy urged the NHRC to conduct a thorough investigation, gather updated data, implement targeted policies, and ensure justice and protection of the rights of the DNT community.

"The allegations, prima facie, indicate serious violations of the human rights of the victims," observed the NHRC Bench, chaired by Priyank Kanoongo. The commission has taken cognizance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Registry has been directed to issue notices to Sundargarh District Magistrate and SP, instructing them to investigate the allegations and submit an ATR.

STATESMAN, Bhubaneswar, 21.5.2025
Page No. 3, Size:(11.44)cms X (13.49)cms.

NHRC seeks ATR on murder of five members of nomad family

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 20 MAY:

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report (ATR) from the Odisha Government on the brutal murder of five people of nomadic tribes in Sundargarh district.

Five members of a nomadic family, including three women, were brutally murdered and five others were kidnapped by a rival group near Karamdihi village of Sadar police limits in Sundargarh district on 29 October last year.

A petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy implored the NHRC to investigate, collect updated data, implement policies, seek reports, and ensure justice and rights for the community.

The Bench of the National Human Rights Commission, presided by Priyank Kanoongo, Member, has taken cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, in the matter.

The Registry is directed to issue a notice to the with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report for perusal of the Commission", NHRC stated in the order.

HINDUSTAN TIMES, Chandigarh, 21.5.2025
Page No. 4, Size:(7.22)cms X (14.05)cms.

Police were inactive at some places: HC panel on Murshidabad riots

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com

KOLKATA: A report by a committee set up by the Calcutta High Court for identification and rehabilitation of victims of anti-Waqf protests-related violence in West Bengal's Murshidabad district said that the local police were "inactive and absent" during the incidents at Dhulian on April 11.

It also mentioned that a local councillor directed the attacks at Dhulian town in Murshidabad.

The report, submitted to the high court by the three-member committee, stated that a garments mall in Dhulian was also looted.

Noting that the "main attack" occurred on the afternoon of April 11, the report said "Local police were completely inactive and absent."The panel, comprising Joginder Singh, Registrar, (Law), National Human Rights Commission (NHRC), Satya Arnab Ghosal, member secretary, West Bengal Legal Services Authority (WBLSA) and Saugata Chakraborty, Registrar, WBJS, submitted the report to the high court last week after visiting the affected areas and speaking to the victims as directed by the division bench hearing the matter.

The high court had on April 17 ordered the formation of the committee for the identification and rehabilitation of people displaced by the violence during the protests over the Waqf (Amendment) Act in Murshidabad district.

The division bench, comprising justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury, noted that the committee had stated in its report that "appointing qualified valuation experts is the only possible remedy to the state's failure to protect a section of its citizens.

"The victims of the affected areas need individualised and customised rehabilitation packages and for this, securing the services of valuation experts appears to be the sine qua non (an essential condition)," it said, according to the court.

Another report earlier submitted by the West Bengal government to the division bench hearing the petitions related to the Murshidabad violence detailed widespread incidents of violence between April 8 and April 12 by mobs in connection with protests over the Waqf Act.

It stated that following intervention by the police and civil administration, the situation in Suti, Dhulian, Samserganj and Jangipur was under control.

JANSATTA, Kolkata, 21.5.2025
Page No. 3, Size:(6.91)cms X (9.15)cms.

मुर्शिदाबाद हिंसा पर समिति की रपट में कहा गया

कुछ स्थानों पर निष्क्रिय थी पुलिस

कोलकाता, 20 मई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की रपट में कहा गया है कि 11 अप्रैल को धुलियान में हुई घटनाओं के दौरान स्थानीय पुलिस 'निष्क्रिय और अनुपस्थित' थी।

रपट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था। तीन सदस्यीय समिति द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपी गई रपट में कहा गया है कि धुलियान में कपड़ों के एक शोरूम में भी लूटपाट की गई थी। मुख्य हमला 11 अप्रैल की दोपहर को होने का जिक्र करते हुए रपट में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी।

समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलएसए) के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं। समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से बात करने के बाद पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय को अपनी रपट सौंपी। सत्रह अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए समिति के गठन का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि समिति ने अपनी रपट में कहा है कि राज्य द्वारा अपने नागरिकों के एक वर्ग की सुरक्षा करने में विफलता में सुधार करने का एकमात्र उपाय मूल्यांकन के लिए योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करना है।

रपट में उल्लेख किया गया है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था। धुलियान में कपड़ों के एक शोरूम में भी लूटपाट की गई थी। मुख्य हमला 11 अप्रैल की दोपहर को होने का जिक्र करते हुए रपट में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। समितिसमिति में एनएचआरसी के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, डब्ल्यूबीएलएसए के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं।

जनसत्ता Wed, 21 May 2025
https://epaper.jansatta.com/c/77407917

JANSANDESH TIMES, Varanasi, 21.5.2025
Page No. 8, Size:(7.01)cms X (5.50)cms.

मानवाधिकार आयोग ने दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

चंदौली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहाबगंज में प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने डीएम चंदौली एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अंतिम रिमाइंडर जारी कर सख्त आदेश देते हुए दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पूरा मामला शहाबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। जहा प्रसव के दौरान संजू देवी ग्राम लाटांव की मौत हो गई थी। मृतका के पति ने आरोप लगाया था पत्नी की मौत डाक्टर संदीप गौतम एवं स्टॉप नर्स की लापरवाही के कारण हुई है। परिजनों ने डाक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर सड़क भी जाम कर दिया था। मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सीडब्लूए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह योगी ने मामले की शिकायत आयोग में भेजकर दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने एवं मृतिका के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया था। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए ७ नवम्बर २०२४ की कार्यवाही के माध्यम से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपों की जांच करने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने और आयोग को कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सीएमओ चंदौली को मामले में गहन जांच करने और बिना देरी किए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि न्यायालय ने सीएमओ चंदौली को प्रारंभिक जांच के लिए निर्देशित किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित चिकित्सा लापरवाही का कोई कार्य या घटना रिकॉर्ड में आती है या नहीं इससे पहले कि धारा 173 (4) बीएनएसएस के तहत आगे के निर्देश जारी किए जाएं। स्थिति आयोग को प्राधिकरण से जांच रिपोर्ट मांगने से नहीं रोकती है। आयोग के निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने मामले में अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। आयोग ने अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैए पर सख्त कदम उठाते हुए डीएम चंदौली और मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंदौली को अंतिम अनुस्मारक जारी करने का निर्देश जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर रिपोर
प्रसूत करने का निर्देश दिया है।

AMRIT VICHAR, Lucknow, 21.5.2025
Page No. 12, Size:(7.84)cms X (7.14)cms.

मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान कुछ स्थानों पर निष्क्रिय थी पुलिस

कोलकाता, एजेंसी

- कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित की गई समिति की रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की गठित समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि 11 अप्रैल को धुलियान में हुई घटनाओं के दौरान स्थानीय पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। इसमें यह भी उल्लेख है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था।

तीन सदस्यीय समिति ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि धुलियान में कपड़ों के शोरूम में भी लूटपाट हुई थी। मुख्य हमला 11 अप्रैल की दोपहर को होने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलएसए) के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं। समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से बात करने के बाद पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी।

RASHTRIYA SAHARA, Varanasi, 21.5.2025
Page No. 9, Size:(9.05)cms X (31.49)cms.

मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा के दौरान नदारद रही पुलिस

■ कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति ने दी रिपोर्ट

कोलकाता (भाषा)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 अप्रैल को धुलियान में हुई घटनाओं के दौरान स्थानीय पुलिस 'निष्क्रिय और अनुपस्थित' थी।

मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था। तीन सदस्यीय समिति द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि धुलियान में कपड़ों के एक शोरूम में भी लूटपाट की गई थी। 'मुख्य हमला' 11 अप्रैल की दोपहर को होने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार जोगिदर सिह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल है। समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से बात करने के बाद पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

RASHTRIYA SAHARA, Lucknow, 21.5.2025
Page No. 1, Size:(12.29)cms X (7.32)cms.

मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा के दौरान नदारद रही पुलिस

कोलकाता (भाषा)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 अप्रैल को धुलियान में हुई घटनाओं के दौरान स्थानीय पुलिस 'निष्क्रिय और अनुपस्थित' थी।

■ कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति ने दी रिपोर्ट

मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था। तीन सदस्यीय समिति द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि धुलियान में कपड़ों के एक शोरूम में भी लूटपाट की गई थी। 'मुख्य हमला' 11 अप्रैल की दोपहर को होने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सत्य अर्नव घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल है। समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से बात करने के बाद पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

PRABHAT KHABAR, Kolkata, 21.5.2025
Page No. 1, Size:(24.00)cms X (15.20)cms.

मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस निष्क्रिय व अनुपस्थित थी : समिति

एजेंसियां, कोलकाता

मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) कानून विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 अप्रैल को धुलियान में हुई घटनाओं के दौरान स्थानीय पुलिस 'निष्क्रिय और अनुपस्थित' थी.

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था. तीन सदस्यीय समिति द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि धुलियान में कपड़ों के एक शोरूम में भी लूटपाट की गयी थी. 'मुख्य हमला' 11 अप्रैल की दोपहर को होने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 'स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी.' समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलएसए) के सदस्य सचिव सत्य अनंब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं.

समिति ने पिछले सप्ताह हाइकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी. न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 'राज्य द्वारा अपने नागरिकों के एक वर्ग की सुरक्षा करने में विफलता में सुधार करने का एकमात्र उपाय मूल्यांकन के लिए योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करना है.'

The Indian Express

Murshidabad violence: High Court-appointed panel says local police were inactive, absent

The report also mentioned local Trinamool Congress leader Mehboob Alam. “The attacks were directed by the local councillor Mehboob Alam. The local police were completely inactive and absent,” the report said of the violence that took place on April 11.

https://indianexpress.com/article/cities/kolkata/murshidabad-violence-high-court-appointed-panel-says-local-police-were-inactive-absent-10018730/

Written by Tanusree Bose
Kolkata | May 21, 2025 04:25 IST

3 min read

The three-member committee formed by the Calcutta High Court to look into last month’s violence in Murshidabad has said in its report that police were “completely inactive”.

The report also mentioned local Trinamool Congress leader Mehboob Alam. “The attacks were directed by the local councillor Mehboob Alam. The local police were completely inactive and absent,” the report said of the violence that took place on April 11.

The Calcutta High Court had last month directed the formation of a three-member committee to oversee the rehabilitation of those affected by the violence that broke out in Murshidabad between April 8 and 12 following protests against the Waqf Amendment Bill. The committee comprises Joginder Singh, Registrar, National Human Rights Commission; Satya Arnab Ghosal, member secretary, West Bengal Legal Services Authority; and Saugata Chakraborty, Registrar, WBJS.

The committee’s report said that miscreants destroyed a waterbottle shop and looted the cash box containing Rs 12,000-13,000. A shopping mall located in ward no 12 was also completely looted and closed, and 29 shops were affected in Ghoshpara, the report said.

“Residents of Samserganj, Hizaltala, Shiulitala, (and) Digri came masking their faces. Local councillor, namely Mehoob Alam, came with the miscreants on April 11. The MLA was also present on Friday (April 11). He saw the vandalism and went away, but the violence continued on April 12, Saturday,” the report said.

TMC spokesperson Joy Prakash Majumdar told The Indian Express, “We do not know anything about such a report. So, I would not like to make any comment.”

The Calcutta High Court had on Friday directed the TMC government in the state to “remunerate and restore” all parties whose lives and properties were affected during the clashes in Murshidabad. The court was hearing a PIL in connection with the violence that broke out between April 8 and 12 in the Jangipur subdivision of Murshidabad, leading to the deaths of three persons, including a father-son duo.

A Division Bench of Justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury said, “Compensating the victims by giving each of them Rs 1.20 lakh under the scheme ‘Banglar Bari’ may not do justice to all as the damaged and destroyed houses, differing in size and constructional features…” The Bench, in its order, also urged the state to consider appeals by local residents for a permanent Border Security Force (BSF) camp in the area and asked the Special Investigation Team (SIT) to “continue investigating the issue to bring the perpetrators to justice”.

India Today

Murshidabad violence fact-finding committee highlights police absence, inactivity

A three-member fact-finding committee submitted its report to Calcutta High Court on Tuesday. The report highlights the absence and inactivity of the police during the incident.

https://www.indiatoday.in/amp/india/story/murshidabad-violence-fact-finding-committee-highlights-police-absence-inactivity-2727879-2025-05-21

Indrajit Kundu | Kolkata,UPDATED: May 21, 2025 07:48 IST

Edited By: Harshita Das

Subscribe to Notifications

In Short

Fact-finding committee submits reports on Murshidabad violence

Local leader Mehboob Alam accused of directing attacks in Dhuliyan

High Court urges expert valuation for recovery and compensation

The fact-finding committee set up by Calcutta High Court submitted its report on the communal violence that occurred in West Bengal's Murshidabad in highlighting the "inactivity and absence" of police during the incidents at Dhulian on April 11. The report said that Trinamool Congress (TMC) leader Mehboob Alam directed the attacks, sources said.

As per sources, the committee's report states, "Local Councillor send TMC leader Mehboob Alam came with the miscreants on April 11. The MLA is also present on Friday. He saw the vandalism and went away. But the violence continued on April 12, Saturday [Sic]"

"Attacks were directed by the local councillor Mehboob Alam," the report states, adding that local police were "completely inactive and absent".

However, the reference to one Mehboob Alam as a local councillor seems erroneous, as Alam is not a councillor but the former chairman of Dhuliyan Municipality.

The committee â€” comprising Joginder Singh, Registrar (Law), National Human Rights Commission; Satya Arnab Ghosal, Member Secretary, West Bengal Legal Services Authority; and Saugata Chakraborty, Registrar, West Bengal Judicial Service â€” was tasked with identifying and assessing the damages and rehabilitation needs of the victims displaced by the violence.

According to the report, the “main attack” took place after 2:30 pm on April 11 in Dhuliyan town. The attackers allegedly had their faces covered to conceal their identities. The report notes that a garment mall in Dhuliyan was also looted.

The committee documented that "as many as 113 houses were badly affected in the village of Betbona."

"Majority of residents had to take shelter in Malda but all of them have been forced to return by the police administration," the report alleges.

Referring to the murder of Haragovinda Das (74) and his son Chandan Das (40), the report states, "They broke down the main door of the house and took her son [Chandan Das] and took her husband [Haragovinda Das] and hit them with an axe in the back. A man was waiting there until they died."

Temples were also destroyed during the violence, the report said.

According to news agency PTI, the High Court division bench, comprising Justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury, observed that the victims require “individualised and customised rehabilitation packages” and stressed the necessity of “appointing qualified valuation experts” for effective recovery and compensation.

Earlier, the West Bengal government had submitted a report to the court indicating widespread violence between April 8 and April 12 linked to protests over the Waqf (Amendment) Act, 2025. The government' report stated that following intervention by the police and civil administration, the situation in Suti, Dhulian, Samserganj and Jangipur was under control.

With PTI inputs

Times of India

`Police inactive and absent': What are key findings of HC-appointed panel on Murshidabad violence

https://timesofindia.indiatimes.com/india/police-inactive-and-absent-what-are-key-findings-of-hc-appointed-panel-on-murshidabad-violence/articleshow/121297343.cms

TIMESOFINDIA.COM | May 20, 2025, 11.33 PM IST

'Police inactive and absent': What are key findings of HC-appointed panel on Murshidabad violence

NEW DELHI: A report by three-member committee set up by Calcutta high court to investigate the anti-Waqf protests in Murshidabad that turned violent has pointed to serious lapses by local authorities in West Bengal. The report noted that the "main attack" took place on April 11 and the "local police were completely inactive and absent". It further alleged that a local councilor played a key role in orchestrating the attacks in Dhulian town.

The high court on April 17 directed the formation of a committee to identify and rehabilitate those displaced by the violence. During the protests over the Waqf Act, a father and son — Harogobindo Das and Chandan Das — were discovered brutally murdered with multiple stab wounds at their home in Shamsherganj's Jafrabad locality. The panel—comprising Joginder Singh (Registrar, Law, NHRC), Satya Arnab Ghosal (Member Secretary, WBLSA), and Saugata Chakraborty (Registrar, WBJS)—submitted its report to the Calcutta high court last week.

Key findings of the committee:

"Main attack" occurred on the afternoon of April 11, the report alleged.

A local councillor directed the attacks at Dhulian town in Murshidabad, it said.

"Local police were completely inactive and absent," it said.

The report said that victims in the affected areas required tailored rehabilitation packages, and engaging valuation experts to ensure appropriate support and compensation.

Meanwhile, an earlier report submitted by the West Bengal government to the division bench outlined widespread mob violence in Murshidabad between April 8 and April 12, linked to protests against the Waqf Act.

The report noted that protests over the Waqf (Amendment) Act, 2025 began on April 4 across all police station areas in Jangipur police district. It added that the situation in Suti, Dhulian, Samserganj, and Jangipur was eventually brought under control through the intervention of the police and civil administration.

It said that the protests escalated into violence starting April 8. On April 12, a mob killed Haragobinda Das and his son Chandan Das in Jafrabad under Samserganj police station.

As the situation deteriorated, central forces were deployed in Samserganj on April 11, followed by additional CAPF deployments on April 12, ordered by the high court.

The riots had sparked a political row with Bharatiya Janata Party (BJP) claiming that "Hindu families" were targeted. The Trinamool Congress chief and Bengal CM Mamata Banerjee had alleged that the violence was "orchestrated and well planned".

Deccan Herald

Murshidabad violence: Calcutta HC appointed panel says police were inactive at some places

The High Court had on April 17 ordered the formation of the committee for the identification and rehabilitation of people displaced by the violence during the protests over the Waqf (Amendment) Act in Murshidabad district.

https://www.deccanherald.com/india/west-bengal/murshidabad-violence-calcutta-hc-appointed-panel-says-police-were-inactive-at-some-places-3549471

PTI Last Updated : 20 May 2025, 20:59 IST

Kolkata: A report by a committee set up by the Calcutta High Court for identification and rehabilitation of victims of anti-Waqf protests-related violence in West Bengal's Murshidabad district said that the local police were "inactive and absent" during the incidents at Dhulian on April 11. It also mentioned that a local councillor directed the attacks at Dhulian town in Murshidabad. The report, submitted to the high court by the three-member committee, stated that a garments mall in Dhulian was also looted. Noting that the "main attack" occurred on the afternoon of April 11, the report said "Local police were completely inactive and absent." The panel, comprising Joginder Singh, Registrar, (Law), National Human Rights Commission (NHRC), Satya Arnab Ghosal, member secretary, West Bengal Legal Services Authority (WBLSA) and Saugata Chakraborty, Registrar, WBJS, submitted the report to the high court last week after visiting the affected areas and speaking to the victims as directed by the division bench hearing the matter. The high court had on April 17 ordered the formation of the committee for the identification and rehabilitation of people displaced by the violence during the protests over the Waqf (Amendment) Act in Murshidabad district.

The division bench, comprising justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury, noted that the committee had stated in its report that appointing qualified valuation experts is the only possible remedy to the state's failure to protect a section of its citizens. "The victims of the affected areas need individualised and customised rehabilitation packages and for this, securing the services of valuation experts appears to be the sine qua non (an essential condition)," it said, according to the court. Another report earlier submitted by the West Bengal government to the division bench hearing the petitions related to the Murshidabad violence detailed widespread incidents of violence between April 8 and April 12 by mobs in connection with protests over the Waqf Act. It stated that following intervention by the police and civil administration, the situation in Suti, Dhulian, Samserganj and Jangipur was under control. The report said that agitational programmes over the Waqf (Amendment) Act, 2025 started on April 4 in all police station areas of Jangipur police district in Murshidabad district. It stated that the protests turned violent from April 8.

The report said that two persons - Haragobinda Das and his son Chandan Das - were killed by a mob on April 12 at Jafrabad under Samserganj police station. It stated that central forces were deployed in Samserganj on April 11 as the situation went out of control, and thereafter more CAPF were deployed on orders of the high court on April 12.

Hindustan Times

Murshidabad violence: HC-appointed panel says police were inactive at some places

https://www.hindustantimes.com/india-news/murshidabad-violence-hc-appointed-panel-says-police-were-inactive-at-some-places-101747753764834.html

PTI | May 20, 2025 08:39 PM IST

Murshidabad violence: HC-appointed panel says police were inactive at some places

Kolkata, A report by a committee set up by the Calcutta High Court for identification and rehabilitation of victims of anti-Waqf protests-related violence in West Bengal's Murshidabad district said that the local police were "inactive and absent" during the incidents at Dhulian on April 11.

It also mentioned that a local councillor directed the attacks at Dhulian town in Murshidabad.

The report, submitted to the high court by the three-member committee, stated that a garments mall in Dhulian was also looted.

Noting that the "main attack" occurred on the afternoon of April 11, the report said "Local police were completely inactive and absent."

The panel, comprising Joginder Singh, Registrar, , National Human Rights Commission , Satya Arnab Ghosal, member secretary, West Bengal Legal Services Authority and Saugata Chakraborty, Registrar, WBJS, submitted the report to the high court last week after visiting the affected areas and speaking to the victims as directed by the division bench hearing the matter.

The high court had on April 17 ordered the formation of the committee for the identification and rehabilitation of people displaced by the violence during the protests over the Waqf Act in Murshidabad district.

The division bench, comprising justices Soumen Sen and Raja Basu Chowdhury, noted that the committee had stated in its report that "appointing qualified valuation experts is the only possible remedy to the state's failure to protect a section of its citizens.

"The victims of the affected areas need individualised and customised rehabilitation packages and for this, securing the services of valuation experts appears to be the sine qua non ," it said, according to the court.

Another report earlier submitted by the West Bengal government to the division bench hearing the petitions related to the Murshidabad violence detailed widespread incidents of violence between April 8 and April 12 by mobs in connection with protests over the Waqf Act.

It stated that following intervention by the police and civil administration, the situation in Suti, Dhulian, Samserganj and Jangipur was under control.

The report said that agitational programmes over the Waqf Act, 2025 started on April 4 in all police station areas of Jangipur police district in Murshidabad district.

It stated that the protests turned violent from April 8.

The report said that two persons - Haragobinda Das and his son Chandan Das - were killed by a mob on April 12 at Jafrabad under Samserganj police station.

It stated that central forces were deployed in Samserganj on April 11 as the situation went out of control, and thereafter more CF were deployed on orders of the high court on April 12.

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

Opindia

TMC Councillor led mob in anti-Hindu carnage as police stood down: Calcutta HC probe in Murshidabad violence reveals

The report states that the violence, which coincided with the passage of the Waqf Amendment Bill, was targeted at members of the Hindu community and resulted in extensive damage to life and property.

https://www.opindia.com/2025/05/tmc-councillor-led-mob-in-anti-hindu-carnage-police-inactive-calcutta-hc-probe-in-murshidabad-violence-reveals/

20 May, 2025 | OpIndia Staff

A report submitted by a fact-finding committee constituted by the Calcutta High Court has implicated a leader of the ruling Trinamool Congress (TMC) in the communal violence that erupted in Murshidabad last month. The report states that the violence, which coincided with the passage of the Waqf Amendment Bill, was targeted at members of the Hindu community and resulted in extensive damage to life and property.

The committee, comprising members of the National Human Rights Commission (NHRC), the West Bengal State Legal Services Authority, and the Judicial Services, conducted field visits to affected areas, including Betbona, Samserganj, Hizaltala, and Shiulitala. The findings were presented before a division bench of the Calcutta High Court.

Key Findings

Involvement of Political Figures:

The report identifies local TMC councillor Mehboob Alam as having led a group of miscreants involved in the attack. It also names Amirul Islam, who allegedly directed the mob to properties that had not yet been attacked, prompting further arson.

Police Inaction:

The local police are reported to have been “completely inactive and absent” during the violence. Calls for help from the villagers of Betbona reportedly went unanswered. The incident occurred within a 300-metre radius of the local police station, yet no intervention was made.
Additionally, a Member of the Legislative Assembly (MLA) was allegedly present during the attacks but did not attempt to prevent or stop the violence.

Extent of Damage:

According to the report:

113 homes in Betbona village were severely damaged and rendered uninhabitable.

Water connections were deliberately severed to prevent residents from extinguishing fires.

Victims, particularly women, have taken refuge with relatives due to fear and lack of shelter.

Casualties and Communal Targeting:

On April 12, a Hindu man and his son were killed by their Muslim neighbours, the report noted. The violence that followed led to the destruction of several businesses and places of worship.

Looting and Arson of Commercial Properties:

Twenty-nine shops were affected in Ghoshpara.

A mall-style shopping complex was looted and shut down.

Grocery stores, hardware shops, textile outlets, and temples were destroyed.

The report concludes that the violence was organized and communal in nature, with clear political involvement and failure of law enforcement to protect citizens. The findings are likely to intensify the political debate in the state and raise serious concerns regarding the state's response to communal unrest and the politicization of local governance structures.

The High Court is expected to deliberate further on the report's findings and may consider directing the state government to take appropriate action against those named.

News18

Murshidabad Violence: दंगाई मचाते रहे उत्पात, ममता की पुलिस ने साधे रखी चुप्पी, कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा

https://hindi.news18.com/amp/news/nation/murshidabad-violence-on-waqf-law-committee-says-during-dhuliyan-riots-police-inactive-local-councilor-ordered-attack-reports-ws-l-9253933.html

Edited by: Sandeep Gupta Agency:भाषा Last Updated:May 20, 2025, 23:34 IST

समिति ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर रिपोर्ट दी, जिसमें 11 अप्रैल को धुलियान में पुलिस की निष्क्रियता और स्थानीय पार्षद की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था. वक्फ कानून के विरोध में यह दंगे हुए थे.

हाइलाइट्स

मुर्शिदाबाद हिंसा पर पुलिस की निष्क्रियता उजागर.

स्थानीय पार्षद ने हमलों का निर्देश दिया था: सूत्र

हाईकोर्ट के आदेश पर समिति का गठन किया गया था.

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के पीड़ितों की पहचान और पुनर्वास के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर एक समिति का गठन किया गया था. इस समिति की रिपोर्ट में बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के आधीन आने वाली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए गएह हैं. रिपोर्ट में साफ-साफ शब्दों में कहा गया कि मुर्शिदाबाद पुलिस ने दंगों को रोकने के लिए अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसके कारण स्थिति लगातार खराब होती चली गई.

पार्षद के कहने पर धूलपुर में हमला

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 अप्रैल को धुलियान में हुई घटनाओं के दौरान स्थानीय पुलिस “निष्क्रिय और अनुपस्थित” थी. इसमें यह भी बताया गया कि मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश एक स्थानीय पार्षद ने दिया था. तीन सदस्यीय समिति द्वारा हाईकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि धुलियान में कपड़ों के एक शोरूम में भी लूटपाट की गई थी. मुख्य हमला 11 अप्रैल की दोपहर को होने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी. समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलएसए) के सदस्य सचिव सत्य अर्नब घोषाल और डब्ल्यूबीजेएस के रजिस्ट्रार सौगत चक्रवर्ती शामिल हैं.

कोर्ट ने अपनाया था सख्त रुख

समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से बात करने के बाद पिछले सप्ताह हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी. 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए समिति के गठन का आदेश

दिया था. न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि "राज्य द्वारा अपने नागरिकों के एक वर्ग की सुरक्षा करने में विफलता में सुधार करने का एकमात्र उपाय मूल्यांकन के लिए योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करना है."

Amar Ujala

Murshidabad: अमर उजाला की रिपोर्ट पर मुहर; अदालत की जांच समिति ने कहा- हिंदुओं को निशाना बनाया, पुलिस मूकदर्शक

https://www.amarujala.com/india-news/murshidabad-violence-calcutta-high-court-probe-committee-report-tmc-leader-role-wb-police-silence-know-details-2025-05-20?pageId=1

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 21 May 2025 06:03 AM IST

सार

देश

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंसा के समय राज्य की पुलिस मूकदर्शक बनी रही। जांच समिति के मुताबिक हिंसा में तृणमूल नेता शामिल रहे। विधायक के सामने ही घरों में आग लगाई गई। इस रिपोर्ट के सामने आते ही अमर उजाला की रिपोर्ट पर भी मुहर लगी है।

विस्तार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पिछले महीने भड़की हिंसा में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक नेता शामिल था। हिंसा के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इस दौरान पुलिस कहीं मूकदर्शक बनी रही, तो कहीं मौके पर नहीं पहुंची। हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में यह हिंसा भड़की थी।

अमर उजाला की रिपोर्ट पर जांच समिति की मुहर

मुर्शिदाबाद हिंसा पर अमर उजाला ने बेदवना की वेदना शीर्षक से 20 अप्रैल को रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें बेदवना गांव में 113 घरों को जलाने की बात कही गई थी, जांच समिति ने इसका अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है।

Hindustan

हिंदुओं पर होते रहे हमले, सोई रही पुलिस; बंगाल हिंसा पर HC की रिपोर्ट में TMC पर नई आंच

कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में बनी जांच समिति ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में टीएमसी नेता पर हिंसा की साजिश रचने और पुलिस पर आंखें मूंदने के आरोप लगे हैं।

https://www.livehindustan.com/national/hindus-attacked-police-missing-tmc-leader-name-surfaced-in-high-court-investigation-into-bengal-violence-201747748780109.html

20 मई 2025

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते महीने हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में गठित जांच समिति ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का एक नेता भी शामिल था। हिंसा उस समय भड़की जब वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया जा रहा था और हमले का निशाना खासतौर पर हिंदू समुदाय के लोग बने। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब पीड़ित लोगों ने मदद के लिए पुलिस को पुकारा, तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया।

एनडीटीवी के मुताबिक, जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुर्शिदाबाद के स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने खुद इन हमलों का नेतृत्व किया। वह शुक्रवार 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के बाद बदमाशों के साथ गांव में पहुंचे और फिर आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ का तांडव शुरू हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि बेटबोना गांव में 113 घर बुरी तरह प्रभावित हुए और वहां दुकानोंमें जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई।

पुलिस रही नदारद: रिपोर्ट

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय और मौके से नदारद थी। इस रिपोर्ट को आज कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने पेश किया गया। जांच टीम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में क्या अगला कदम उठाता है।

Telangana Today

Telangana: National Human Rights Commission expresses anger on Sircilla collector

National Human Rights Commission expressed anger at the collector, Sandeep Kumar Jha, for submitting a weak report on the death of an aged woman, who was killed by dogs in Sevalal thanda

https://telanganatoday.com/telangana-national-human-rights-commission-expresses-anger-on-sircilla-collector

By Raghu Paithari

Published Date - 21 May 2025, 12:43 AM

Rajanna Sircilla: National Human Rights Commission expressed anger at the collector, Sandeep Kumar Jha, for submitting a weak report on the death of an aged woman.

NHRC informed to use its powers to present the collector before the commission personally.

It may be recalled here that an elderly woman, Pitla Ramalakshmi (82), was killed by dogs and ate her body parts in Sevalal thanda of Mustabad mandal on August 1, last year.

Based on the complaint lodged by an advocate, Emmadi Rama Rao, NHRC has taken up an investigation and sought a comprehensive report from the collector on the incident.

Not satisfied with the report submitted by the collector, the commission expressed anger at him for submitting a feeble report.

Jammulinksnews

GDC Ramgarh hosts Poster Making Competition on Mental Healthcare

https://www.jammulinksnews.com/mob/newsdet.aspx?q=386168

20/05/2025

Jammu Links News

SAMBA: Government Degree College Ramgarh organized a Poster Making Competition on the theme "Mental Healthcare Act, 2017" today under the purview of the National Human Rights Commission (NHRC).

The event was held under the guidance of the Principal of the college, Prof. (Dr.) Meeru Abrol.

The competition was meticulously organized by Priya Sharma, who played a key role in coordinating the event and encouraging student participation.

The objective of the competition was to raise awareness about mental health rights and to sensitize students on the significance of the Mental Healthcare Act, 2017, which ensures the protection and dignity of individuals with mental illness.

Students from different semesters took part in the event with great enthusiasm, showcasing their understanding through creative and impactful posters. Ashu Verma secured the first prize, while Chetna Sanotra and Amandeep Kaur won the second and third prizes respectively.

The event was judged by Prof. Sandeep Kumari and Dr. Shivali Panjgotra, who praised the participants for their originality, clarity of message and artistic skills. Faculty members including Dr. Aditi Khajuria, Dr. Snobar, Ashok Kumar, Dr. Neeraj Bargotra, Anjali Devi and Sayma were also present and supported the smooth conduct of the event.

Hindustan Hindi

एमजीएम अस्पताल दुर्घटना मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कोरिडोर गिरने से चार मरीजों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों पर आपराधिक...

https://www.livehindustan.com/jharkhand/jamshedpur/story-national-human-rights-commission-takes-notice-of-mgm-medical-college-hospital-corridor-collapse-and-patient-deaths-201747721088509.amp.html

20 मई 2025

जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कोरिडोर गिरने एवं चार मरीजों की मौत मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शिकायत वाद दर्ज किया है। इस मामले में आयोग ने झारखंड मानवाधिकार संगठन (जेएचआरसी) के प्रमुख मनोज मिश्रा को जानकारी दी है। मनोज मिश्रा ने बताया कि अस्पताल का कोरिडोर गिरने के मामले पर उन्होंने आयोग से शिकायत करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। उसमें पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कहा गया था। मनोज मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत झारखंड उच्च न्यायलय एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी की है।

मनोज मिश्रा ने सवाल उठाया है कि साकची स्थित करीब 70 वर्ष पुराने जर्जर अस्पताल बिल्डिंग से डिमना में बने नए अस्पताल भवन में मरीजों को समय रहते क्यों शिफ्ट नहीं किया गया। इस बड़ी लापरवाही के कारण चार निर्दोषों की जान गयी, इसकी जबाबदेही तय होनी चाहिए। इससे जुड़े दोषियों पर हर हाल में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण विभाग ने तीन वर्ष पूर्व इसी पुराने बिल्डिंग में रिपेयर का काम किया था। उसके बाद भी उन्होंने पुराने बिल्डिंग की जर्ज़र अवस्था को लेकर अबतक कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाया, यह बड़ा सवाल है।

Navbharat Times

आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, ट्रस्ट ने की शिकायत

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/agra/agra-karni-sena-workers-allege-police-brutality-complaint-filed-with-human-rights-commission-news/articleshow/121289525.cms

Compiled by: ऐश्वर्य कुमार राय|नवभारतटाइम्स.कॉम•20 May 2025, 3:29 pm

Agra Sena: करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने शिकायत की है। ताज सुरक्षा एसीपी अरीब अहमद और खैरागढ़ एसीपी इमरान अहमद पर आरोप लगाए गए हैं।

सुनील साकेत, आगरा: क्षत्रिय संगठन करणी सेना के कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। करणी सेना की ओर से क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट ने अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। आगरा पुलिस पर कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता करने और मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का आरोप लगाया है। ट्रस्ट ने एसीपी ताज सुरक्षा अरीब अहमद और अन्य पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि 14 मई को करणी सेना के अध्यक्ष ओकेंद्र राणा किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नौफरी आए थे। ओकेंद्र राणा के जाने के बाद एसीपी अरीब अहमद पुलिसकर्मियों के साथ गांव में पहुंच गए थे। दबिश देकर 11 युवकों को हिरासत में ले लिया। उन्हें ताजगंज की एकता चौकी पर ले जाया गया। जहां उनके साथ मारपीट की गई। जिसमें कई युवकों को गंभीर चोटें आईं। महाराणा प्रताप के नाम अर्नगल नारेबाजी की गई।

पुलिस के सामने ही निकल गया था राणा

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि ओकेंद्र राणा गांव के किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। वह गाड़ी में बैठकर पुलिस के सामने से निकल गया था। इसके बाद पुलिस ने गांव की महिलाओं के साथ अभद्रता की और 11 युवाओं को पकड़कर एकता पुलिस चौकी ले गए। युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कई धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।

एसीपी अरीब और इमरान अहमद पर आरोप

क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता का कहना है कि हिंदू युवाओं को जानबूझकर टारगेट किया गया। नौफरी से पहले खेरागढ़ में करणी सेना के कार्यकर्ता विवेक सिकरवार को एसीपी खेरागढ़ के इशारे पर गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप लगाया गया था कि किसी संघेय अपराध को कारित कर सकता है। जबकि तलाशी में उसके पास मोबाइल ही निकला था। उसे जेल भेज दिया गया।